

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वित्तीय संस्थाओं में विद्यमान क्षेत्रीय विषमताएँ

—डॉ. जैशराज शुक्ल

एसो. प्रो. (भूगोल विभाग)

का.सु. साकेत, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादकता गतिविधियों विशेषरूप से लघु व्यवसायों तथा सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों, दस्तकारों और उनसे सम्बन्धित अन्य गतिविधियों को व्यावहारिक रूप में विकसित करने तथा सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।¹ वित्त एवं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वित्तीय संस्थाओं से अभिप्राय उन संस्थाओं से है, जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं जैसे—ग्राहकों का धन जमा रखना, ग्राहकों को ऋण देना, बैंक ड्राफ्ट देना, निधि अन्तरण आदि प्रदान करते हैं। किसी भी देश की प्रगति में वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वित्तीय संस्थानों का मुख्य कार्य देश में मुद्रा के प्रवाह को नियन्त्रित करना होता है, साथ ही साथ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं।² पूर्वी उत्तर प्रदेश में वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्गत बैंकों तथा साधन सहकारी समितियों को सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र—

पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने मातृ प्रदेश (उत्तर प्रदेश) के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में स्थित है। विकास की दृष्टि से यह एक पिछड़ा क्षेत्र है, किन्तु संसाधन विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह गंगा-घाघरा मैदान का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाये गये अवसादों के निक्षेप से निर्मित है। इसके उत्तर में भारत, नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पायी जाती है। पूर्व में बिहार तथा झारखण्ड राज्य दक्षिण में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं द्वारा सीमांकित है। अध्ययन क्षेत्र के पश्चिम में खीरी-लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा फतेहपुर जनपद इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23°51' उत्तर से 28°31' उत्तरी अक्षांश तक तथा देशान्तरीय विस्तार 81°30' पूर्वी से 84°39' पूर्वी देशान्तर के मध्य पाया जाता है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 86548 वर्ग किमी⁰ है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.11 प्रतिशत है। प्रशासनिक संरचना की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 मण्डल, 28 जनपद, 128 तहसीलें तथा 362 विकास खण्ड हैं। उत्तर-दक्षिण में इसकी लम्बाई 550 किमी⁰ तथा पूर्व-पश्चिम में चौड़ाई 395 किमी⁰ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 79889303 थी, जिसमें 40917356 पुरुष व 38971947 महिलाएं थी। कुल जनसंख्या का 88 प्रतिशत गाँवों में तथा 12 प्रतिशत नगरों में निवास करती है। अध्ययन क्षेत्र की कुल साक्षरता 66 प्रतिशत थी। वर्ष 2017-18 में सम्भाग में प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता 80, उच्च प्राथमिक विद्यालय 39 तथा माध्यमिक विद्यालय 15 पाये गये।

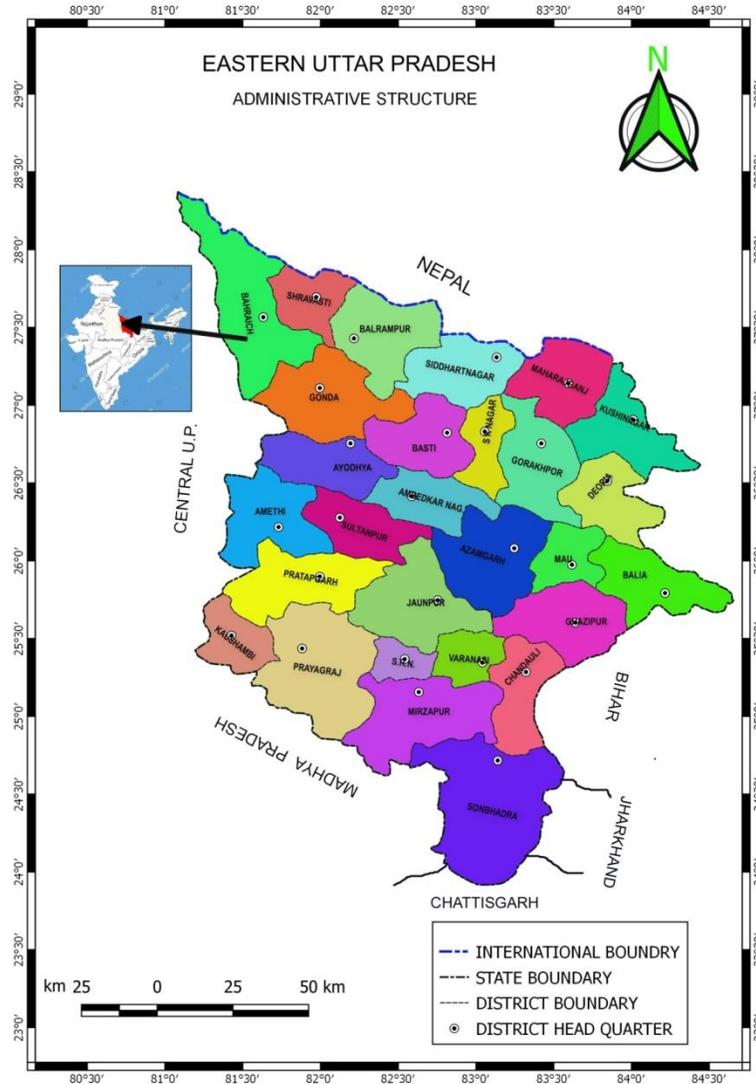


Fig.1

शोध प्रविधि-

प्रस्तुत शोध पत्र मूलतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं में विद्यमान विषमता के विश्लेषण के लिए जनपद स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ अध्ययन क्षेत्र में साधन सहकारी समितियों का भी विश्लेषण किया गया है। इसके लिए वर्ष 2007-08 एवं 2017-18 के आँकड़ों का संकलन किया गया है। आँकड़ों का संकलन जनपदों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय पत्रिकाओं से किया गया है। अध्ययन को उपयोगी बनाने के लिए कुछ सांख्यिकीय

विधियों जैसे— मध्यमान, मानक विचलन तथा विभिन्नता गुणांक की गणना की गयी है। इसी आधार पर अध्ययन क्षेत्र में विद्यमान क्षेत्रीय विषमताओं का विश्लेषण किया गया है।

बैंक—

पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति सौ वर्ग किमी० पर बैंकों की उपलब्धता के विवरण को सारिणी-1 में दर्शाया गया है। सारिणी से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के समस्त जनपदों को बैंकों की उपलब्धता के आधार पर चार वर्गों अति निम्न, निम्न, मध्यम तथा उच्च में वर्गीकृत किया गया है। अति निम्न वर्ग में वे जनपद पाये गये, जहाँ वर्ष 2007-08 में प्रति सौ वर्ग किमी० पर बैंकों की उपलब्धता तीन से कम पायी गयी। इस वर्ग में श्रावस्ती, बलरामपुर तथा सोनभद्र जनपद शामिल थे। जिन जनपदों में इनकी उपलब्धता 3 से 5 के मध्य पायी गयी, उनको निम्न वर्ग में रखा गया है। इसमें 11 जनपद समाहित हैं, जो कुल जनपदों का 40.74 प्रतिशत है, जबकि मध्यम वर्ग में 10 जिले बस्ती, देवरिया, आजगढ़, मऊ, गाजीपुर, अयोध्या, प्रयागराज, संतरविदासनगर तथा जौनपुर पाये गये। इन जनपदों में प्रति सौ वर्ग किमी० पर बैंकों की उपलब्धता 5 से 7 के मध्य पायी गयी है। उच्च वर्ग में उन जनपदों को रखा गया है, जहाँ इनकी उपलब्धता सात से अधिक पायी गयी है। इस वर्ग में गोरखपुर, बलिया तथा वाराणसी जनपद आकलित किये गये हैं।

सारिणी-1 पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैंकों की उपलब्धता (प्रति सौ वर्ग किमी०)

वर्ग	आन्तरिक मूल्य	2007-08		आन्तरिक मूल्य	2017-18	
		जनपद की सं.	कुल जनपद का प्रतिशत		जनपद की सं.	कुल जनपद का प्रतिशत
अति निम्न	3 – कम	3	11.11	6 – कम	6	21.43
निम्न	3 – 5	11	80.74	6 – 8	6	21.43
मध्यम	5 – 7	10	37.04	8 – 10	9	32.14
उच्च	7 –अधिक	3	11.11	10 –अधिक	7	25.00
योग—		27	100.00	योग—	28	100.00
S.V.- 2008		Mean= 5.18		S.D. = 2.65		C.V.=57.19%
S.V. -2018		Mean= 9.16		S.D. = 5.14		C.V.=56.14%

Source:- District Statistical Bulletin-2008 & 2018

वर्ष 2017-18 में भी समस्त जनपदों को चार वर्गों में बाँटा गया है। जिन जनपदों में प्रति सौ वर्ग किमी० पर बैंकों की उपलब्धता 6 से कम पायी गयी, उनको अति निम्न वर्ग में रखा गया है। इसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र व मिर्जापुर जनपद शामिल है। निम्न वर्ग में गोण्डा, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, चन्दौली तथा प्रतापगढ़ जिले पाये गये। इनमें उपलब्धता 6 से 8 के बीच थी। मध्यम वर्ग (8 से 10) में नौ जनपद सम्मिलित किये गये, जो कुल जनपदों का 32.14 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र के उन जनपदों को उच्च वर्ग में रखा गया है, जहाँ प्रति सौ वर्ग किमी० पर बैंक शाखाओं की उपलब्धता 10 से अधिक पायी गयी है। इस श्रेणी में सात जनपद गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, संतरविदासनगर, वाराणसी और कौशाम्बी पाये गये। अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 में बैंक शाखाओं का औसत 5.18 था, जो दस वर्षों बाद वर्ष 2017-18 में बढ़कर 9.16 हो गया। अध्ययन क्षेत्र में वर्ष

2007-08 में विभिन्नता गुणांक 57.19 प्रतिशत थी, जो आंशिक ह्रास के साथ वर्ष 2017-18 में 56.14 प्रतिशत पायी गयी, जो उच्च स्तरीय क्षेत्रीय विषमता को दर्शाता है। मानचित्र-2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती जनपदों में बैंकों की उपलब्धता अधिक तथा उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में कम पायी गयी है।

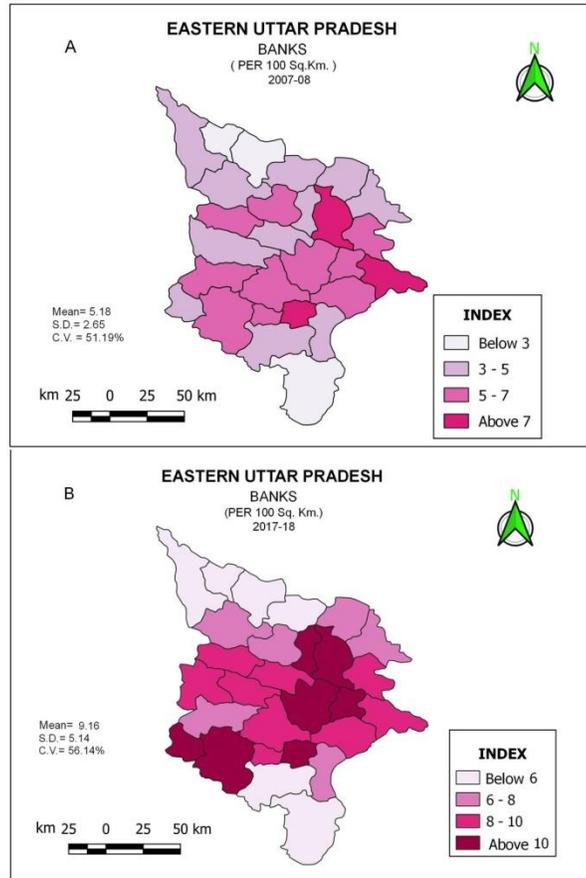


Fig.2

साधन सहकारी समितियाँ—

कृषि के विकास में साधन सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये समितियाँ कृषकों को सस्ते दर पर खाद तथा बीजों को उपलब्ध कराती हैं, साथ ही साथ इनके उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर खरीदती हैं, जिससे कृषकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होता है। इन समितियों के द्वारा कृषकों को खाद तथा बीज के लिए ऋण भी प्रदान किये जाते हैं, जिससे किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।³ कृषि समितियों की उपलब्धता के आधार पर समस्त जिलों का चार वर्गों में बाँटा गया है,

जिसे सारिणी-2 तथा मानचित्र-3 में दर्शाया गया है। सारिणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 में तीन जनपद बलरामपुर, मिर्जापुर तथा सोनभद्र अति निम्न वर्ग में पाये गये। यही जनपद 2017-18 में इसी वर्ग में भी पाये गये। इन जनपदों में प्रति सौ वर्ग किमी⁰ पर साधन सहकारी समितियों की उपलब्धता दो से कम पायी गयी है।

सारिणी-2 पूर्वी उत्तर प्रदेश में साधन सहकारी समितियों की उपलब्धता (प्रति सौ वर्ग किमी⁰)

वर्ग	आन्तरिक मूल्य	2007-08		आन्तरिक मूल्य	2017-18	
		जनपद की सं.	कुल जनपद का प्रतिशत		जनपद की सं.	कुल जनपद का प्रतिशत
अति निम्न	2 - कम	3	11.11	2 - कम	3	10.71
निम्न	2 - 4	9	33.33	2 - 4	7	25.00
मध्यम	4 - 6	12	44.45	4 - 6	15	53.58
उच्च	6 -अधिक	3	11.11	6 -अधिक	3	10.71
योग-		27	100.00	योग-	28	100.00
S.V.- 2008		Mean= 4.26		S.D. = 1.52		C.V.=35.86%
S.V. -2018		Mean= 4.31		S.D. = 1.49		C.V.=34.51%

Source:- District Statistical Bulletin-2008 & 2018

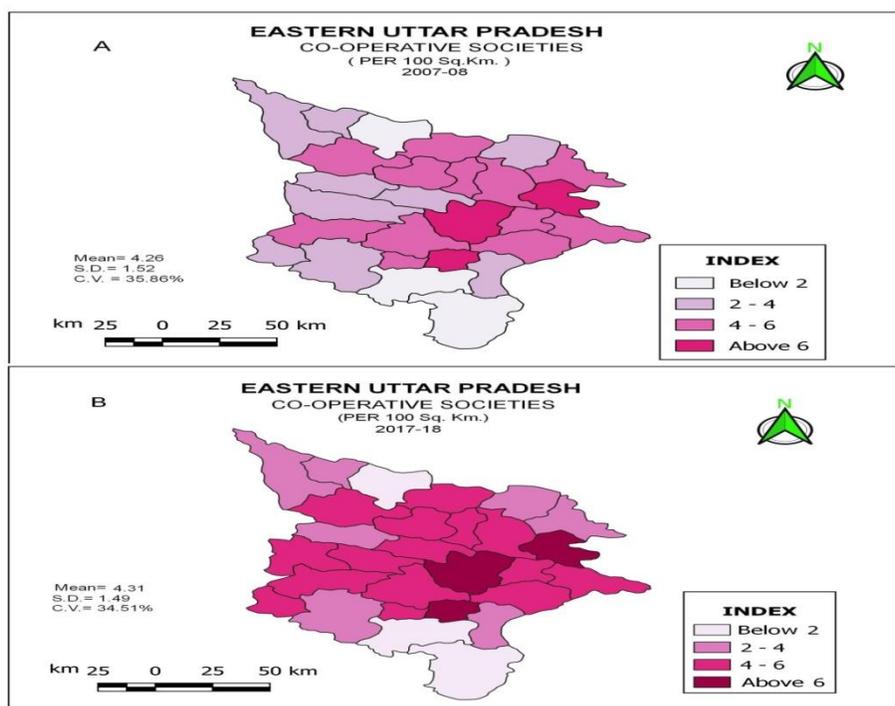


Fig. 3

निम्न वर्ग में वे जनपद आते हैं, जहाँ प्रति सौ वर्ग किमी⁰ पर साधन सहकारी समितियों की संख्या 2 से 4 के बीच पायी गयी। इस वर्ग में वर्ष 2007-08 में 9 जनपद तथा 2017-18 में सात जनपद पाये गये, जो कुल जनपदों का 25.0 प्रतिशत है। साधन सहकारी समितियों के मध्यम वर्ग में उन जनपदों को रखा गया है, जहाँ इनकी संख्या 4 से 6 के मध्य पायी गयी है। इस वर्ग में वर्ष 2007-08 में 12 जिले पाये गये, जो कुल जनपदों का 44.45 प्रतिशत थे, जबकि वर्ष 2017-18 में इस वर्ग में जनपदों की संख्या बढ़कर 15 हो गयी, जो कुल जनपदों का 53.58 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र के वे जनपद जहाँ इनकी उपलब्धता 6 से अधिक पायी गयी है, उनको उच्च वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग में दोनों वर्षों में तीन-तीन जनपद पाये गये हैं। वर्ष 2017-18 में इसमें देवरिया, आजमगढ़ तथा वाराणसी जनपद शामिल हैं।

अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2007-08 में साधन सहकारी समितियों का औसत 4.26 था, जो आंशिक वृद्धि के साथ 4.31 हो गया। समितियों के संदर्भ में क्षेत्रीय विषमता में आंशिक कमी आयी, फिर भी इसमें मध्यम स्तरीय विषमता विद्यमान है। वर्ष 2007-08 में विभिन्नता गुणांक 35.86 प्रतिशत थी, जो घटकर 34.51 प्रतिशत हो गयी है।

निष्कर्ष एवं सुझाव-

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैंक शाखाओं के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि दस वर्षों की समयावधि में वृद्धि हुई है, परन्तु इनके वितरण में बड़ी असमानता पायी गयी है। नगरों तथा महानगरों में बैंकों की उपलब्धता अधिक पायी गयी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी कमी देखी गयी है। अतः क्षेत्रीय विषमता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार केन्द्रों पर बैंक शाखाओं को खोलने की आवश्यकता है, जिससे कृषक, छोटे व्यापारी और छोटे दुकानदारों आदि को आसानी से ऋण मिल सके तथा बचत को सुरक्षित अपने खातों में रख सकें। साधन सहकारी समितियों की उपलब्धता में दस वर्षों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। क्षेत्रीय विषमता भी पर्याप्त पायी गयी है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में साधन सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को मिलने वाले सुविधाएं उपलब्ध कराके कृषि विकास किया जा सकता है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है।

References :

- 1- Shukla, D.K. (2010): Regional Disparties in Rural Development in Raebareli District U.P. unpublished Ph.D. Thesis Dr. R.M.L. Avadh University Faizabad. P.171
- 2- <https://hi.m.wikipedia.org>.
3. Shrivastava, P.K. (2011) : Socio-Economic Change Rural Development of Parasrampur Block (District Basti): A Geographical Analysis unpublished Ph.D. Thesis Dr. R.M.L. Avadh University Faizabad.P. 185.